

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
लैंक रोड नं. 3, भोपाल - 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्र./VC/428168/I/1319249/2026

दिनांक : 21-09-2026

प्रति,

समस्त संयुक्त/उप संचालक,
 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
 मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 09/09/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक 09/09/2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय तथा जिलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

- मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में सर्वप्रथम दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की गई। विभाग में कुल 51 शिकायतें लंबित पाई गई, जिसमें उमरिया(8), भिण्ड(6), छिन्दवाडा(5), ग्वालियर(4), बालाघाट(4), भोपाल(4), शिवपुरी(3), खण्डवा(2), जबलपुर(2), पन्ना(2), मुरैना(2), अशोक नगर(1), छतरपुर(1), दमोह(1), नर्मदापुरम(1), नीमच(1), पांडुरंगा(1), मंदसौर(1), मण्डला(1) एवं विदिशा(1) में शिकायतें लंबित पाई गई। संबंधित जिला अधिकारियों को उक्त शिकायतों का तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- भिण्ड, विदिशा, भोपाल, पांडुरंगा, ग्वालियर एवं उमरिया जिलों में लंबित निम्न शिकायतों पर शिकायतवार चर्चा की गई एवं तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये। जिला भिण्ड में एक ही आवेदक द्वारा 3 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। उक्त तीनों शिकायतें क्रमशः 250, 179 एवं 108 दिनों से लंबित हैं। जिला भिण्ड को निर्देशित किया गया कि समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम दिनांक 11.09.2026 में जिला धार में भी उक्त प्रकृति की शिकायत का चयन किया गया है। अतः प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

क्र.	शिकायत क्रमांक	नाम	जिला	लंबित दिवस
1	36165825	धीरज सिंह	भिण्ड	250
2	37227397	धीरज सिंह	भिण्ड	179
3	38520387	लक्ष्मी	भिण्ड	108
4	40209595	नसीम	विदिशा	16
5	39375257	शेख अब्दुल	भोपाल	62
6	37534124	दिनेश	पांडुरंगा	162
7	39997439	मोहन सिंह	ग्वालियर	28
8	39983604	विनोद कुमार	उमरिया	28

- विभाग की हितग्राही मूलक संवेदनशील योजनाओं यथा दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष उपकरण प्रदान योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना , दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। भोपाल (108), विदिशा (30) , जबलपुर (29),

उमरिया (26), सागर (26), छिन्दवाडा (24), भिण्ड (22), शिवपुरी (20), बालाघाट (15), शहडोल (15), कटनी (14), ग्वालियर (14), छतरपुर (14), पन्ना (13), दमोह (12) में उक्त योजनाओं की सर्वाधिक शिकायतें लंबित पाई गई। संबंधित जिला अधिकायियों को उक्त शिकायतों का तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. विभाग की लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के प्राप्त समय-सीमा बाह्य आवेदनों की समीक्षा की गई एवं तत्काल समय-सीमा बाह्य लंबित आवेदनों का निराकरण करवाने के निर्देश दिये गये। भिण्ड एवं ग्वालियर जिलों में समय सीमा बाह्य लंबित आवेदन लंबित पाये गये। समस्त जिलों को समय-सीमा बाह्य प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये। समस्त जिलों को अवगत कराया गया कि वरिष्ठ स्तर से नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन कर लंबित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कराने के निर्देश दिये गये जिससे कोई भी प्रकरण समय सीमा बाह्य लंबित ना हो।

S.N	Registration No.	Name	District	Target Date	Scheme
1	RS/420/2602/104/2026	उर्मिला शर्मा	Bhind	7/9/2026	IGNOAPS
2	RS/420/2619/52/2026	रचना दोहरे	Bhind	24/08/2026	kalyani Pension
3	RS/420/2619/54/2026	सुमन देवी सेन	Bhind	8/9/2026	kalyani Pension
4	RS/421/2603/3/2026	राज कौर	Gwalior	8/9/2026	IGNWPS

5. विभिन्न पोर्टलों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा :-

विभिन्न विभागीय पोर्टलों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

- पेंशन पोर्टल पर निर्णय हेतु लंबित आवेदन : जिला **BHIND, DHAR, CHHATARPUR, GWALIOR एवं REWA** में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाए तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का विशेष प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- पेंशन पोर्टल पर **DSC Sign** हेतु लंबित प्रकरण : जिला **BHOPAL, UJJAIN, BETUL, BHIND एवं SHIVPURI** में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने के तत्काल उपरांत DSC Sign की कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।
- पेंशन हितग्राहियों को माह जुलाई 2026 में हुए असफल भुगतान : माह में कुल असफल भुगतान की संख्या के आधार पर जिला **SAGAR (2241), JABALPUR (1964), INDORE (1867), BALAGHAT (1804) एवं REWA (1644)** में सर्वाधिक असफल भुगतान पाए गए। साथ ही 12 माह से सतत असफल भुगतान की संख्या के आधार पर जिला **SAGAR (224), MANDSAUR (215), INDORE (151), RATLAM (156) एवं UJJAIN (142)** में अधिक प्रकरण पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि असफल भुगतान के प्रत्येक प्रकरण का कारणवार परीक्षण कर तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला **BALAGHAT, VIDISHA, CHHINDWARA, GWALIOR एवं ANUPPUR** में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

- **दिव्यांग विवाह योजना :** लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला **RAJGARH, MANDSAUR, SEONI, DHAR एवं BALAGHAT** में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार समय-सीमा में स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- **मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना :** वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कुल लंबित प्रकरणों की संख्या के आधार पर जिला **BHOPAL, RAISEN, UJJAIN, BALAGHAT एवं CHHATARPUR** में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि समस्त लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- **कल्याणी विवाह योजना :** लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला **VIDISHA, CHHATARPUR, CHHINDWARA, MORENA एवं SAGAR** में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का समय-सीमा में परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरणों पर e-Sign की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पात्र हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा भुगतान की प्रविष्टि विवाह पोर्टल पर दर्ज की जाए।
- **कन्या विवाह/निकाह योजना :** दिनांक **01.04.2024** से **09.09.2026** तक की स्थिति की समीक्षा के दौरान लाभ हेतु लंबित पात्र हितग्राहियों की संख्या के आधार पर जिला **SAGAR (1095), UMARIA (802), VIDISHA (777), SATNA (683) एवं KATNI (597)** में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित पात्र हितग्राहियों के भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

6. UDID पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा :-

UDID पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। कुल **18,322** आवेदन लंबित पाए गए। जिला-वार समीक्षा में **JABALPUR, CHHATARPUR, INDORE, DAMOH एवं BHOPAL** में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

7. e-HRMS - Online ACR की समीक्षा :-

e-HRMS पोर्टल पर Online ACR की प्रगति की समीक्षा की गई। Self Appraisal Form जनरेट किए जाने हेतु जिला **JABALPUR (59), BHOPAL (57), UJJAIN (52), GWALIOR (51) एवं INDORE (47)** में सर्वाधिक प्रकरण शेष पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि शेष कर्मचारियों के Self Appraisal Form जनरेट किए जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

8. WP-1405/2025 जाने कौशिक विरुद्ध भारत सरकार एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी Questions के संबंध में :-

WP-1405/2025 जाने कौशिक विरुद्ध भारत सरकार एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी Questions के संबंध में समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारी को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

9. आपराधिक अपील (CRA) क्रमांक 4604/2025 प्रहलाद प्रसाद विश्वकर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 11.08.2026 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में :-

उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 11.08.2026 को पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा सभी जिला अधिकारियों को प्रतिमाह 16 तारीख के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

10. Transgender Protection Cell एवं जिला Transgender Board के गठन की समीक्षा :-

जिला रीवा-मऊगंज में जिला स्तरीय Transgender Board का गठन नहीं किया गया है। साथ ही विभिन्न जिलों में Transgender Protection Cell के गठन एवं गठित Transgender Board की आयोजित बैठकों की जानकारी की समीक्षा की गई। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय Transgender Board का गठन तत्काल सुनिश्चित करते हुए Transgender Protection Cell एवं बोर्ड की बैठकों की अद्यतन जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए।

11. भारत सरकार की SMILE-Beggary Scheme एवं SNA Sparsh के संबंध में :-

भारत सरकार की SMILE-Beggary Scheme अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, छतरपुर (खजुराहो), खण्डवा (ओंकारेश्वर), जबलपुर, भोपाल, रतलाम, अनूपपुर (अमरकंटक), निवाड़ी (ओरछा), खरगोन (महेश्वर), सतना (चित्रकूट) एवं ग्वालियर के प्रस्ताव E-Anudan पोर्टल पर अपलोड कराए जाने की समीक्षा की गई। साथ ही भारत सरकार से प्राप्त Mother Sanction के अंतर्गत SNA Sparsh के माध्यम से जिला स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में निर्देश दिए गए।

12. जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर DLC (Digital Life Certificate) के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणन की समीक्षा :-

जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर DLC (Digital Life Certificate) मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणन की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान DLC Registration Pending की स्थिति में **SAGAR (65,530), BALAGHAT (48,874), CHHATARPUR (46,715), DAMOH (43,253)** एवं **MANDSAUR (42,868)** में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। साथ ही **RATLAM (37,052), BHOPAL (33,642), REWA (29,187), GUNA (28,297)** एवं **JABALPUR (26,846)** में भी बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित पाए गए प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यलय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
(म.प्र.)

क्र./VC/428168/I/1319249/2026

दिनांक : 21-09-2026

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
6. समस्त जिला समन्वयक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी - सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
8. समस्त समग्र संयोजक - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।

कार्यलय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)